एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा देश की खाद्य परीक्षण सुविधाओं का सशक्तीकरण

भारत में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के शीघ्र उन्नयन की आवश्यकता के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) ने ₹ 482 करोड़ की लागत से देश में खाद्य परीक्षण सुविधाओं को सशक्त बनाने की एक बड़ी योजना आरंभ की है।

इस कार्य के लिए गठित प्राधिकार समिति ने अपनी पहली बैठक 2 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में की, जिसकी अध्यक्षता एफ.एस.एस.ए.आई के अध्यक्ष ने की और जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, निर्यात निरीक्षण परिषद्, एन.ए.बी.एल और 7 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में गोआ, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिल नाडु और पंजाब सात राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की खाद्य परीक्षण सुविधाओं को सशक्त बनाने के प्रस्तावों पर विचार किया गया। चंडीगढ़ (पंजाब) और कालिकट (केरल) के दो प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमति दे दी गई। शेष राज्यों को एफ.एस.एस.ए.आई से सहयोग लेते हुए योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने प्रस्तावों की पुनरीक्षा करके उन्हें पुन: प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। समिति ने अधुनातन उपकरणों और सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई) की रेफरल खाद्य प्रयोगशाला को सशक्त बनाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया। इन उपकरणों की सुविधाओं से शहद में अपमिश्रण और खाद्य नमूनों में पेस्टीसाइड और एंटीबायोटिकों के अवशिष्टों की परीक्षण क्षमता बढ़ाने में महत्वूपर्ण सहायता मिलेगी।

इस योजना के अंतर्गत 45 राज्य/संघ शासित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र में कम से कम एक और बड़े राज्यों में 2 प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित) और 14 रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल प्रत्यायन हेतु उन्नत किया जाएगा। सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में 62 चल परीक्षण प्रयोगशालाएँ भी स्थापित की जाएँगी। वर्तमान में पंजाब, गुजरात, केरल और तमिल नाडु में 4 चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं, जो इन चल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए मॉडल का काम करेंगी। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का क्षमता-निर्माण करना भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। इनके अतिरिक्त, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आहार की संस्कृति पनपाने के लिए एक 'स्कूल खाद्य और स्वच्छता कार्यक्रम' आरंभ करने का विचार भी है, जिसके अंतर्गत देश भर के 1500 स्कूलों/कालेजों में आधारभूत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँगी।